विधानसभा का बजट सत्र 16 से

12 बैठकें होंगी

6 मार्च तक चलेगी

19 फरवरी को पेश हो सकता है वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 15 जनवरी. मप्र विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से आहूत किया गया है. 6 मार्च तक चलने वाले 19 दिवसीय सत्र में कुल 12 बैठकें होंगी. इस अवधि में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश होगा. मिले संकेतों के मुताबिक बजट 19 या 20 फरवरी को पेश हो सकता है.

इसमें प्रदेश की आर्थिक सेहत की नई तस्वीर पेश होगी. सत्र के पहले सप्ताह में पांच दिन तक लगातार बैठकें होंगी, फिर दो दिन अवकाश के बाद 23 से 27 तक भी लगातार बैठकें होंगी. इस दौरान विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. 28 फरवरी से 4 मार्च तक होली अवकाश रहेगा. मार्च में सदन की महज दो बैठकें ही होंगी. यह तब होगा, जब सदन सामान्य रूप से संचालित हो. लेकिन इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से सेवन से 23 लोगों की मौत के बाद प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है. ऐसे में विपक्ष इस मामले को सदन में प्रमुखता से उठा सकता है. यदि इस मामले में सदन की कार्यवाही बाधित हुई तो फिर कार्यवाही होली अवकाश से पहले भी अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जा सकती है. वहीं बजट को पारित कराने के लिये गिलोटिन का सहारा लिया जा सकता है. पिछले बजट सत्र में भी सभी विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं हो सकी थी.

> बजट सत्र के लिये गुरुवार को विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगुभाई पटेल का अभिभाषण होगा. राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर दो दिन की चर्चा हो सकती है, जिसका जवाब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देंगे. वहीं बजट पर भी दो दिन की सामान्य चर्चा हो सकती है. बजट पेश करने से एक दिन पहले प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा.

श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा की अंतिम तारीख बढ़कर हुई

भोपाल, 15 जनवरी. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं स्कूल शिक्षा विभाग के मध्य रूह. के माध्यम से संचालित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए पूर्णतया नि:शुल्क श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या को प्रोत्साहित करने प्रवेश परीक्षा की अंतिम तारीख 20 जनवरी से बढ़ाकर 28 जनवरी कर दी गई है। श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 वीं से 9 वीं तक सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन 08 फरवरी 2026 को है। शासकीय श्रमोदय आवासीय वि ?द्यालय जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल एवं इंदौर में अधिक से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 28 जनवरी तक कर दी गई है।

हाईकोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

- वर्चुअल रूप से पेश हुए मुख्य सचिव और एडवोकेट जनरल
- भागीरथपुरा मामले की अगली सुनवाई 20 को

नव भारत न्यूज

इंदौर, 15 जनवरी. भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई मौतों के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अनुराग जैन और एडवोकेट जनरल प्रतापसिंह वर्चुअल रूप से कोर्ट के समक्ष पेश हुए और अब तक की गई प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी दी. साथ ही कहा कि आगे जैसा कोर्ट आदेश देगा, उसका पालन किया जाएगा.

मुख्य सचिव ने आज हाईकोर्ट में जस्टिस विनय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की डबल बेंच को बताया कि मामले में लापरवाही के चलते अपर आयुक्त, अधीक्षण यंत्री और सहायक यंत्री को निलंबित कर दिया गया है. जबकि उप यंत्री की सेवा समाप्त करने के साथ आईएएस निगम आयुक्त को हटाने की कार्रवाई की गई है. उनकी जगह निगम में एक जिम्मेदार आईएएस को नियुक्त किया है.

मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है. दूषित पानी से बीमार हुए सभी मरीजों का सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज कराया जा रहा है. कोर्ट ने मुख्य सचिव जैन से मौत का आंकड़ा पूछा, तो मुख्य सचिव ने 15 लोगों की मौत होना स्वीकार किया. साथ ही अन्य बीमारियों से 8 लोगों की मौत होना बताया. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें कई पहले से अन्य दूसरी बीमारियों (को-मोरबिडिटी) से ग्रस्त थे. हाईकोर्ट ने शासन से पूरे मामले की स्थिति को स्पष्ट करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने इस प्रकरण में अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी तय की है. मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है कि दूषित पाने से कितने लोगों की मौत हुई है. अगली तारीख पर भी मुख्य सचिव को वर्चुअल उपस्थित होने को कहा गया है.

शासन के जवाब पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

उल्लेखनीय है कि भागीरथपुरा में जहरीले पानी से 23 मौत हो चुकी है और प्रशासन द्वारा 21 लोगों को राहत राशि दी गई है. पिछली सुनवाई में अदालत ने शासन के जवाब को असंवेदनशील बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई थी और कहा था कि स्वच्छ पेयजल नागरिकों का मौलिक अधिकार है. कोर्ट यह भी स्पष्ट कर चुका है कि आवश्यकता पडऩे पर जिम्मेदार अधिकारियों की सिविल और आपराधिक जवाबदेही तय की जा सकती है, वहीं मुआवजे को लेकर भी अदालत हस्तक्षेप कर सकती है.

जिला स्तरीय शैक्षिक ओलम्पियाड का आयोजन आज और कल

- जन शिक्षा केन्द्र स्तर के 2 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल
- सभी विकासखंड मुख्यालयों पर होगी परीक्षा

भोपाल, 15 जनवरी. प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत कक्षा 2 से 8 के विद्यार्थियों के जिला स्तरीय (द्वितीय चरण) शैक्षिक ओलम्पियाड का आयोजन 16 और 17 जनवरी को होगा।

यह प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय पर होगा। इस शैक्षिक ओलम्पियाड में जनशिक्षा केन्द्र स्तर के लगभग 2 लाख विजेता विद्यार्थी सहभागिता करेंगे।

इस शैक्षिक ओलम्पियाड अंतर्गत जनशिक्षा केन्द्र स्तर की परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 नवंबर को प्रदेश के समस्त जनशिक्षा केन्द्र के परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न हुआ था। राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित यह ओलम्पियाड प्रतियोगिता ओएमआर शीट आधारित है। प्रतियोगिता विकासखंड मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी।

मंत्री राजपूत ने सुनीं कार्यकर्ताओं की समस्याएं

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 15 जनवरी. प्रदेश के मंत्रियों के भाजपा कार्यालय पहुंचकर प्रदेशभर से आने वाले कार्यकर्ताओं की शिकायतें और समस्याएं सुनने के क्रम में गुरुवार को प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत भाजपा कार्यालय पहुंचें. यहां वे कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और उनकी शिकायतों और समस्याएं सुनकर उनका निवारण भी किया.

बाद में मीडिया से चर्चा में राजपूत ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल द्वारा कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की एक अत्यंत सराहनीय और दूरदर्शी व्यवस्था शुरू की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश शासन के मंत्रीगण पार्टी की भावना और कार्यकर्ताओं की जनसमस्याओं के अनुरूप प्रत्येक माह निर्धारित दिवस पर प्रदेश कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यकर्ताओं से संवाद करें. इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं की जनसमस्याओं को सुनना, समझना और समाधान हेतु यथासंभव ठोस प्रयास करना है.

दूषित पानी से लोग पड़ रहे बीमार

ग्वालियर, 15 जनवरी. दूषित पानी की सप्लाई के मामले में ग्वालियर में हालात बिगड़ रहे हैं. अधिकांश इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है. जिसके चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं.

इसके अलावा जहां थोड़ा बहुत पानी साफ आ रहा है. तो वहां भी पानी में टीडीएस की मात्रा 500 पीपीएम से भी अधिक है. कई लोग दिल्ली एम्स में भर्ती कराए गए हैं. वार्ड क्रमांक 12 की लाइन नंबर 8 में दूषित पानी के साथ ही हाई टीडीएस पानी भी पहुंच रहा है. पानी में टीडीएस की मात्रा 500 से 700 पीपीएम तक देखने को मिली है. इस पानी को पीने योग्य नहीं माना जाता है. एक निवासी विष्णु तोमर ने बताया कि इसी पानी के चलते वे बीमार हो गए. जब स्थिति गंभीर हो गई तो परिजन दिल्ली एम्स लेकर गए.जहां डॉक्टरों ने कहा कि दूषित पानी पीने के कारण ही सारी समस्या हुई है. अभी भी इलाज हो रहा है.एक अनय निवासी की बेटी का इलाज चल रहा है. उधर नगर निगम का कहना है कि स्वच्छ पानी प्रदाय के लिए निगम संकल्पित है.

पतंगबाजी के दौरान जन-सुरक्षा के लिए रेलवे का अभियान

भोपाल. पतंग उड़ाने के मौसम को देखते हुए भोपाल रेल मंडल आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष जन-सुरक्षा अभियान संचालित कर रहा है. अभियान के माध्यम से लोगों को रेलवे ट्रैक, पुलों एवं ओवरहेड विद्युत तारों के समीप पतंग उड़ाने से होने वाले गंभीर खतरों के प्रति सतर्क किया जा रहा है. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे लाइनों के ऊपर लगी ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन के कारण जानलेवा दुर्घटनाएं घटित होने की आशंका रहती है.

मुरैना में हथियारों का जखीरा पकड़ा

12 पिस्टल बरामद, खरगोन से 10 हजार में लाकर 60 हजार में बेचते थे

मुरैना, 15 जनवरी. बानमौर थाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने भैरव मंदिर मोड़ सीतापुर जाखौदा के पास से इन आरोपियों को दबोचा. इनके कब्जे से 32 बोर की 12 पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस और 8 मैगजीन जब्त की गई हैं, जिनकी कुल कीमत 3 लाख 78 हजार रुपए बताई गई है.

तस्करों ने बताया कि वे खरगोन जिले से 10 से 15 हजार रुपए में पिस्टल खरीदते थे और उसे ग्वालियर और मुरैना में 50 से 60 हजार रुपए में बेचते थे. गिरोह में खरीदकर लाने से लेकर बेचने तक के सभी एजेंट अलग-अलग काम करते थे. बेचने के लिए लोकल एजेंट काम करते थे.पकड़े गए आरोपियों में ग्वालियर और मुरैना के बदमाश शामिल हैं. इन पर पहले से कई अपराध दर्ज हैं. आरोपियों की पहचान भानू गौड निवासी गायत्री मंदिर के पास पुराना जौरा, मोनू उर्फ मोहन उर्फ पप्पू गुर्जर निवासी पगारा रोड जौरा मुरैना, रामलखन कुशवाह निवासी डीडी नगर ग्वालियर, विवेक उर्फ माफिया निवासी गंगाराम का पुरा बानमौर और राज पुत्र पूरन गोस्वामी के रूप में हुई है.

बीना में कांग्रेस महिला विंग का धरना प्रदर्शन

बीना. बीना विधानसभा क्षेत्र के खिमलासा इलाके में एक तीन वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और अमानवीय अत्याचार की घटना के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ ने शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को धरना-प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया है. यह धरना दोपहर 12.30 बजे अंबेडकर चौराहा, बीना में आयोजित होगा, जिसके उपरांत संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा. यह आंदोलन महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका किरार के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है.

कड़ाके की ठंड का असर बरकरार

भोपाल, 15 जनवरी. मध्यप्रदेश में कड़ाके की सर्दी का असर बरकरार है, हालाकि उत्तरी अंचल के अलावा शेष क्षेत्रों में लोगों को कोहरे और धुंध से राहत मिल गयी है. दिन में मौसम शुष्क होने के कारण लोगों को ठंड से काफी राहत है, लेकिन रात्रि में तेज ठंड का दौर जारी है.

मौसम केंद्र के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहा. इस अवधि में शाजापुर जिले में शीतलहर का प्रभाव रहा. दिन का सबसे अधिक तापमान नर्मदापुरम में 30.3 डिग्री और रात्रि का सबसे कम यानी न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री शहडोल जिले के कल्याणपुर और शाजापुर जिले के गिरवर में दर्ज किया गया.

राज्य में न्यूनतम तापमान 4.6 से 14 डिग्री के बीच और अधिकतम तापमान 21 से 30 डिग्री के मध्य रिकार्ड हुआ. ये तापमान लगभग सामान्य हैं. राज्य में कहीं भी मावठा गिरने की सूचना नहीं है.

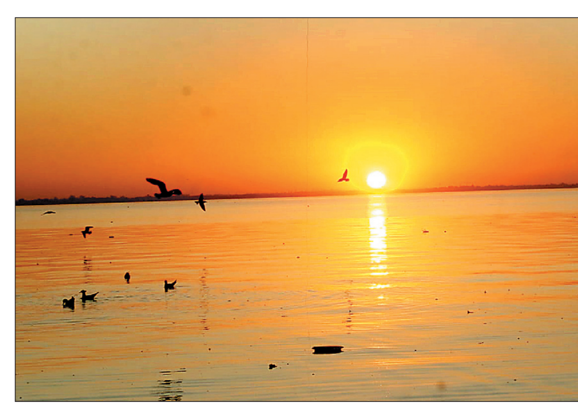

> केंद्र ने बताया कि राज्य में अगले एक दो दिनों के बाद कड़ाके की ठंड का एक और दौर आने की संभावना है. तब रात्रि के तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है. बताया गया है कि पश्चिम उत्तर भारत के ऊपर समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊंचाई पर उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं. एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी मध्य एवं ऊपरी क्षोभमंडलीय क्षेत्र में ट्रफ के रूप में मौजूद है. एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के 19 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है.

संस्कृत, शोध और समाज के सहारे आगे बढ़ेगी भारतीय ज्ञान परंपरा

- शिक्षा का भारतीयकरण, मप्र की अभिनव पहल

भोपाल, 15 जनवरी. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा को उच्च शिक्षा, शोध और समाजोपयोगी गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दो दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया.

बैठक में भारतीय ज्ञान परंपरा को व्यवहारिक, शोधपरक और समाजोपयोगी स्वरूप देने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए विस्तृत कार्ययोजना पेश की गई. बैठक में शामिल विषय विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि अब विश्वविद्यालयों को अपने-अपने विषय के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े कार्यों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखते हुए शोध, लेखन और सामाजिक उपयोगिता से भी जोड़ना होगा. विद्वानों ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित शोध में संस्कृत विद्वानों की भूमिका महत्वपूर्ण है.

बैठक में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में निहित ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में उपयोगी बनाने के लिए उनके अनुवाद और विषयानुकूल अध्ययन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया.

मनासा में जीबीएस का खौफ : 11 संक्रमित, 2 की मौत

- प्रभावित इलाकों में पहुंची डब्ल्यूएचओ की टीम
- स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, घर-घर सर्वे शुरू

मनासा, 15 जनवरी. मनासा क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से गंभीर बीमारी 'गुलियन बेरे सिंड्रोम' (जीबीएस) ने पैर पसारना शुरू कर दिया है. अब तक इस बीमारी से पीड़ित 11 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई है.

उज्जैन संभाग और जिला स्वास्थ्य विभाग ने अब मोर्चा संभाल लिया है. गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने भी प्रभावित वार्डों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के उपसंचालक डॉ. संजय कुमरावत एवं जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मनासा में आपात बैठक भी बुलाई.

> 'जीबीएस संक्रमित बीमारी नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है. बस सावधानी बरतें और पानी उबालकर पिएं. लक्षण दिखते ही चिकित्सक को दिखाएं, समय पर इलाज ही बचाव है.'
> **डॉ. संजय कुमरावत,** उप संचालक, स्वास्थ्य विभाग (उज्जैन)

पानी के सैंपल लिए, अफवाहों से बचने की अपील

डब्ल्यूएचओ टीम के प्रभारी डॉ. रितेश बजाज ने प्रभावित क्षेत्रों से पानी के सैंपल एकत्र किए हैं. डॉ. बजाज के अनुसार, '18 वर्षों के अनुभव में देखा गया है कि कई बार इस बीमारी के लक्षण शुरुआती स्तर पर स्पष्ट नहीं होते. हालांकि, यह छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसलिए मरीजों का सामाजिक बहिष्कार न करें.' उन्होंने बताया कि समय पर इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन लगने से मरीज की जान बचाई जा सकती है.

विवाहित बेटी की हत्या का नहीं है पछतावा

- ऑनर किलिंग का आरोपी पिता पुलिस गिरफ्त में

भिंड, 15 जनवरी. यहां के खिरिया थापक गांव में बीती रात गोली मारकर अपनी नवविवाहित बेटी की हत्या करने वाले पिता को अपने किए पर अफसोस नहीं है. मुन्नेश धानुक नाम के व्यक्ति ने बदनामी के डर के चलते अपनी बेटी निधि को मार डाला.

पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान उसने कहा कि बेटी ससुराल जाने को तैयार नहीं थी. समाज में इज्जत खराब हो रही थी, इसलिए उसे मार दिया. मुझे अपनी करनी पर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि बेटी के ऐसे कृत्य के बाद मैं वैसे भी जी नहीं पा रहा था. बेटी की हत्या का आरोपी मुन्नेश आज सुबह से हवालात में गुमसुम बैठा है. उसने रातभर खाना नहीं खाया. सिर्फ एक-दो बार पानी पीया. वह बार-बार अपने आंसू पोंछता रहा. पूछताछ में उसने कहा- मैंने बेटी को बहुत प्यार किया था, लेकिन वह मेरी ही कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी. मैंने उसे बार-बार मनाया कि अपना घर बसाओ, बेकार की बात मत करो, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी.

> घटनाक्रम के मुताबिक, खिरिया थापक निवासी निधि (21) की शादी ग्वालियर के गुड़ागुडी का नाका निवासी देवू धानुक से हुई थी. वह पति के साथ महाराज बाड़ा पर शॉपिंग करने गई थी. वहां छोले-भटूरे खाने के बाद जब पति पानी लेने गया, तो वह गायब हो गई. पति ने ग्वालियर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. बाद में पिता उसे बहला-फुसलाकर गांव लाया और रात में सरसों के खेत में ले जाकर कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी.

भिंड में किसान की गोली मारकर हत्या

भिंड. भिंड के सौरा में खेत पर बने ट्यूबवैल पर किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक के भाई से आरोपियों की पुरानी रंजिश बताई जा रही है. आरोपियों ने मृतक के 11 वर्षीय बेटे पर भी जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने मालनपुर निवासी दो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. 45 वर्षीय राजकुमार उर्फ छुन्ना गुर्जर अपने परिवार के साथ गांव के बाहर खेत पर बने मकान में रहता था. घटना के वक्त वह अपने 11 वर्षीय बेटे शिवम के साथ खेत पर ही था. रात के समय मालनपुर निवासी रूपसिंह धोबी और लक्ष्मण सिंह धोबी वहां पहुंचे और घर पर हमला बोल दिया.

समीक्षा — जल जीवन मिशन के कामों में लापरवाही पर पीएस ने दिखाये कड़े तेवर

तीन एसई और 12 ईई को कारण बताओ नोटिस जारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 15 जनवरी, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पी. नरहरि ने गुरुवार को जल जीवन मिशन के कार्यों की वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने मिशन के कामों में शिथिलता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाया.

उन्होंने 3 अधीक्षण यंत्रियों एवं 13 कार्यपालन यंत्रियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये. साथ ही स्पष्ट किया कि कार्यों की धीमी प्रगति के लिए संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी. प्रदेश के समस्त जिलों के अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री स्तर तक के अधिकारी से जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तार से जानकारी ली. समीक्षा बैठक में एकल नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की प्रगति की जिलेवार समीक्षा की गई. प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि कई जिलों में घरों तक नल कनेक्शन प्रदान किए जाने की गति निर्धारित लक्ष्यों और तय समय-सीमा के अनुरूप नहीं है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावित हो रही है.

प्रमुख सचिव ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि एकल नलजल प्रदाय योजनाओं के तहत शेष बचे कार्यों को निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि नियमित रूप से प्रगति की निगरानी की जाएगी. नरहरि ने कहा कि जल जीवन मिशन राज्य शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि यह योजना केवल भौतिक संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण जनजीवन की गुणवत्ता में सुधार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है.

> **और शिथिलता बरतने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी**
>
> श्री नरहरि अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कार्यों की प्रगति में किसी प्रकार की शिथिलता पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. प्रमुख सचिव ने कहा कि फील्ड स्तर पर समन्वय बढ़ाते हुए गुणवत्ता, समय-सीमा और पारदर्शिता के साथ कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए.